

Title: Requested to complete the pending railway projects in Rajasthan.

श्री गिरधारी लाल भागव (जयपुर) : महोदय, राजस्थान की जो भी रेल की परियोजनाएं भारत सरकार के पास पड़ी हैं, उनको भारत सरकार को शीघ्र स्वीकृत करना चाहिए। अगर शीघ्र स्वीकृत नहीं करेंगे तो उन योजनाओं की लागत बढ़ रही है, ड्यूटी, दोगुनी हो गई है और अब वह तिगुनी हो जाएगी। फिर सरकार मजबूरी में कह देगी कि हम इन योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते। दौसा-गंगापुरसिटी, अजमेर-पुकर, रामगंजमंडी-भोपाल, वीरमगाम-जोधपुर-भिलडी-समदड़-लूणी, लूणी-बाड़मेर-मुनाबाओ, रेवाड़ी-सादुलपुर, श्रीगंगानगर-सरूपसर, लूणी-जोधपुर, लूणी-मारवाड़, फुलेरा-जोधपुर-पीपाड़रोड-बिलाडा, अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़, आगरा फोर्ट-बांदीकुई, फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद, नीमच-रतलाम, मिल्डी-बिरमगाम, गांधीधाम-पालमपुर की परियोजना है। आगरा-बांदीकुई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशरफ साहब जयपुर आने वाले थे, मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ वह वहां नहीं आए, वापस पाकिस्तान चले गए। वहां पर जितना कर सकते थे, उन्होंने किया और अपनी बात कह कर चले गए। देश को कुछ देकर भी नहीं गए।

वे भी आगरा आने थे। आगरा से बांदीकुई का ट्रैक जब देवगौड़ा जी देश के प्रधान मंत्री थे उनके समय में शुरू हुआ। माननीय कलमाड़ी जी उस समय रेल मंत्री थे वे उद्घाटन कर आये लेकिन वह प्रोजेक्ट आज भी अधूरा पड़ा हुआ है।

इसी तरह से भीलवाड़ा-अजमेर का एस्टीमेट स्वीकृत हो गया है लेकिन बजट का प्रावधान नहीं हुआ है। दौसा-गंगापुर का अभी तक सर्वे कार्य ही बहुत लम्बे समय से चल रहा है भूमि अवाप्ति के लिए मात्र 10 लाख रुपये का प्रावधान इस वित्तीय बजट में किया गया है जबकि इसकी 17 करोड़ रुपये की आवश्यकता भूमि अवाप्ति के लिए होगी। शेष परियोजनाएं भी राज्य के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर परियोजनाओं के लिए इनकी स्वीकृति के समय से ही टोकन प्रावधान रखा गया है। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि इन परियोजनाओं के लिए राशि के आवंटन में वृद्धि की जाये। विशेषकर आगरा-बांदीकुई, अजमेर-दौसा-गंगापुरसिटी परियोजनाओं के लिए अधिक राशि आवंटित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आगरा फोर्ट-बांदीकुई के कन्वर्सन के लिए केवल 10 करोड़ रुपया देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वहां पर एक जोनल ऑफिस बनने को था और भारत के उस समय के प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा जी उद्घाटन कर आये। मैंने उस समय कहा था कि आप पत्थर का उद्घाटन कर रहे हैं या कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। जयपुर शहर में एक जोनल ऑफिस बनना जरूरी है। जमीन हमारे विभाग ने दे दी है। क्वार्टर की जगह मौजूद है और जवाहर नगर के पास एक जोनल ऑफिस के लिए जगह दे दी है। उत्तर पश्चिमी जोन की आवासीय योजना के लिए 17.44 हेक्टेयर भूमि अधिगृहित की गयी है और जोन के मुख्यालय के लिए रेलवे ने जवाहर सर्किल के पास की भूमि आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है। इसके लिए राज्य सरकार बहुत सस्ती दर पर जमीन देने के लिए सहमत हो गयी है। स्वायत्तशासन विभाग के जमीन के प्रस्ताव रेलवे को भेज दिये गये हैं तथा रेलवे बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार के जो भी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं मेरा अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र उनको पूरा कराना चाहिए, नहीं तो लागत कीमत बढ़ जाएगी और ये प्रोजेक्ट्स पास नहीं हो सकेंगे। धन्यवाद।